गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 112
दि. 22.08.2025,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

संक्षिप्त समाचार

महाराष्ट्र के पालघर में फार्मास्युटिकल कंपनी में हुआ गैसा रिसाव, 4 लोगों की मौत

महाराष्ट्र के पालघर में तारापुर-बोईसर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक दवा कंपनी में नाइट्रोजन गैस रिसाव से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि सभी पीड़ित नाइट्रोजन गैस के संपर्क में आने के कारण प्रभावित हुए। अधिकारियों के अनुसार, यह दुखद घटना दोपहर में मेडल फार्मा में हुई, जो मुंबई से लगभग 130 किलोमीटर दूर बोईसर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है।

पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने फोन पर की बात, रूस-यूक्रेन युद्ध समेत इन मुद्दों पर हुई चर्चा

(जीएनएस)।

पीएम मोदी ने बातचीत को लेकर एक्स पर जानकारी शेयर की. दोनों नेताओं ने खासतौर पर यूक्रेन और वेस्ट एशिया में जारी संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाओं पर विचार साझा किए और भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने का संकल्प दोहराया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय हालात को लेकर गुरुवार को अहम बातचीत हुई. दोनों नेताओं ने खासतौर पर यूक्रेन और वेस्ट एशिया में जारी संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाओं पर विचार साझा किए और भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने का संकल्प दोहराया.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, 'मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई. हमने यूक्रेन और वेस्ट एशिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर विचार साझा किए और भारतफ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.'

मैक्रों ने भी इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी. उन्होंने हिंदी में लिखी अपनी पोस्ट में बताया, "मैंने अभी-अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत की. हमने यूक्रेन युद्ध पर अपनी स्थितियों का समन्वय किया ताकि एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की ओर बढ़ सकें, यूक्रेन के लिए ठोस सुरक्षा गारंटी और यूरोप की सुरक्षा के साथ. व्यापार संबंधी मुद्दों पर, हमने अपने

वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने और सभी क्षेत्रों में अपनी सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की."

उन्होंने आगे लिखा, "यही हमारी संप्रभुता और स्वतंत्रता की कुंजी है. फरवरी में पेरिस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की निरंतरता में, हम 2026 में नई दिल्ली में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट की सफलता के लिए कार्य कर रहे हैं. एक अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए, हमने 2026 में जी7 की फ्रांसीसी अध्यक्षता और ब्रिक्स की भारतीय अध्यक्षता को ध्यान में रखते हुए निकट समन्वय करने पर सहमति व्यक्त की है." फ्रांस ने बुधवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा लगाए गए यहूदी-विरोधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. पेरिस स्थित एलिसी पैलेस ने इन आरोपों को घृणित और भ्रामक बताया और कहा कि फ्रांस हमेशा अपने यहूदी नागरिकों की सुरक्षा करता आया है और करता रहेगा.

जीएसटी में खत्म होंगे 12%-28% वाले स्लैब, वित्त मंत्रियों के समूह की मंजूरी, आम लोगों को क्या फायदा?

(जीएनएस)।

भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी हो चुकी है। केंद्रीय सरकार और राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह (GoM) ने जीएसटी स्लैब को सरल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मौजूदा चार स्लैब अब केवल दो स्लैब 5% और 18% में बदल दिए जाएंगे। यह कदम टैक्स सिस्टम को आसान, पारदर्शी और कॉम्प्लायंस को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल के मंत्री भी मौजूद थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नया सिस्टम आम जनता, किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए लाभकारी होगा। इसके अलावा हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी में छूट देने का प्रस्ताव भी रखा गया।

स्लैब में कटौती - विस्तार से समझें

GST के मौजूदा सिस्टम में चार टैक्स स्लैब थे - 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन वित्त मंत्रियों के समूह (GoM) की हालिया बैठक में यह तय किया गया कि अब केवल दो स्लैब रहेंगे - 5% और 18%।

पहले की व्यवस्था

5%: जरूरी वस्तुएं जैसे अनाज, दूध, दालें, दवाइयां आदि।

12%: मिड कैटेगरी की चीजें।

18%: आम सेवाएं और सामान।

28%: लक्जरी और सिन गुड्स (शराब, तंबाकू, जुआ आदि)।

नई व्यवस्था

5% स्लैब: अब भी जरूरी सामान और सेवाओं पर लागू होगा। इसमें 12% स्लैब के कई आइटम शामिल कर दिए जाएंगे।

18% स्लैब: आम कैटेगरी के सामान और सेवाओं पर लागू होगा। इसमें 28% स्लैब वाले लगभग 90% 90% सामान शामिल होंगे।

1. 5% स्लैब (कम टैक्स वाला स्लैब) इस स्लैब में जरूरी वस्तुएँ और आम सेवाएँ शामिल हैं। उद्देश्य यह है कि रोजमर्रा के सामान पर टैक्स कम हो और आम आदमी की जेब पर बोझ न पड़े।

भारत दौरे पर पहली बार आएंगे फिजी के पीएम राबुका, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मु से करेंगे मुलाकात

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामामादा राबुका 24-26 अगस्त को वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत का दौरा करेंगे। यह उनका पहला भारत दौरा होगा और इस दौरान वह पीएम नरेन्द्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात करेंगे।

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि फिजी के पीएम सिटिवेनी लिगामामादा राबुका के साथ उनकी पत्नी, सुलुएती राबुका भी होंगी। प्रतिनिधिमंडल में स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के मंत्री रतु एटोनियो लालाबालावु और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

यह प्रधानमंत्री राबुका का पहला भारत दौरा होगा। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री राबुका 25 अगस्त, 2025 को पीएम मोदी के साथ बातचीत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी उनके

सम्मान में एक लंच का आयोजन करेंगे।

फिजी के पीएम के नई दिल्ली में भारतीय विश्व मामलों की परिषद में 'शांति का महासागर' पर एक व्याख्यान देने की उम्मीद है। पीएम राबुका नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मु ने अगस्त, 2024 में फिजी का दौरा किया था।

पीएम मोदी ने 2014 में किया था फिजी का दौर

उल्लेखनीय है कि 19 नवंबर, 2014 को फिजी का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दौरा न केवल भारत-फिजी संबंधों के लिए, बल्कि भारत के सभी प्रशांत द्वीप देशों के साथ संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस दौरे के दौरान फिजी के साथ तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

पौड़ी का सेब अब दुबई में भी महकेगा, जानिए क्यों खास है किंग रोट किस्म का सेब, ये है प्लानिंग

उत्तराखंड के पौड़ी का सेब अब दुबई में भी महकेगा। इसके बाद सेब के साथ बासमती, मोटे अनाज, शहद, फल व सब्जियों पर भी फोकस किया जाएगा। देहरादून से दुबई के लिए 1.2 मीट्रिक टन गढ़वाली सेब की पहली खेप रवाना की गई।

पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों में उगने वाले सेब, विशेष रूप से किंग रोट किस्म, अपने कुरकुरेपन, स्वाद और प्राकृतिक मिठास के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बावजूद, बागवानों को अक्सर अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचने में आधारभूत ढाँचे, संपर्क और फसल-उपरांत प्रबंधन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

ट्रम्प के टैरिफ तनाव के बीच पुतिन से मिले जयशंकर

(जीएनएस)।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान भारत ने रूस के साथ द्विपक्षीय व्यापार के महत्व पर जोर दिया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत-रूस संबंधों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सबसे स्थिर रिश्तों में से एक बताया। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है।

जयशंकर ने रूसी कंपनियों से भारतीय भागीदारों के साथ अधिक गहनता से काम करने की अपील की। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार को और अधिक विविध बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने लॉजिस्टिक बाधाओं को दूर करने और गैर-टैरिफ रुकावटें हटाने की बात कही।

वहीं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी भारत-रूस संबंधों को

किन-किन अहम मुद्दों पर हुई बात

एक विशेष रणनीतिक साझेदारी करार दिया। जयशंकर ने कहा कि लावरोव के साथ उनकी बैठक राजनीतिक संबंधों और द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा का एक अच्छा अवसर थी।

विदेश मंत्री ने रूस के फर्स्ट डिप्टी पीएम डेनिस मंटुरोव के साथ भी बातचीत की। इस दौरान नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, नॉर्दर्न सी रूट और चेन्नई-व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। जयशंकर ने कहा कि उनका मंत्र 'अधिक करना और अलग तरीके से करना' होना चाहिए।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी बातचीत की थी। इस बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में जब उनसे अमेरिकी शुल्कों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अमेरिका के तर्क पर सवाल उठाया। जयशंकर ने कहा कि वे इस तर्क को लेकर "बेहद हैरान" हैं।

मोदी सरकार रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रही है और चीन के साथ भी संबंध सुधारने पर काम कर रही है। यह सब तब से हो रहा है जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी नई, अंदरूनी व्यापार और विदेश नीति के तहत भारत पर सबसे अधिक शुल्क लगाए थे। रूस जाने से पहले, जयशंकर ने नई दिल्ली में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी।

वर्तमान में, भारतीय निर्यात पर 25% अमेरिकी शुल्क प्रभावी हो चुका है, और इस महीने के अंत तक 25% का एक और "जुमार्ना" शुल्क लगने वाला है। इस स्थिति ने भारत की "संतुलन साधने" की रणनीति को उजागर किया है, जिसमें वह पुतिन को "मित्र" बता रहा है और चीन के साथ संबंध मजबूत कर रहा है।

तेल आयात के मामले में भारत रूस से तेल खरीदने में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, लेकिन अमेरिका ने अभी तक चीन पर ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री ने हाल ही में इसे यह कहकर सही ठहराया था कि चीन के विपरीत, भारत ने युद्ध के बाद रूसी तेल आयात में भारी वृद्धि की है और वह तेल को फिर से बेचकर "मुनाफा कमा" रहा है।

जयशंकर ने लावरोव के साथ संयुक्त ब्रीफिंग में इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा, "हम एक ऐसा देश हैं जिसे अमेरिकी पिछले कुछ सालों से कह रहे हैं कि वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए, जिसमें रूस से तेल खरीदना भी शामिल है। संयोग से, हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं, और उसकी मात्रा बढ़ी है। इसलिए, ईमानदारी से कहें तो, हमें उस तर्क पर बहुत हैरानी है जिसका आपने (मीडिया ने) जिक्र किया।"

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में व्लादिमीर पुतिन की प्रशंसा और बीजिंग के साथ दिल्ली के नए सिरे से जुड़ाव से संकेत मिलता

मध्य प्रदेश में सियासी भगदड़, आधे कांग्रेसी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में वापसी को बेताब!

मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल हुए कांग्रेसी नेताओं में से आधे अब अपनी पुरानी पार्टी में वापसी की जुगत में हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी और महासचिव डॉ संजय कामले ने वरिष्ठ पत्रकार रवि जैन के साथ विशेष बातचीत में यह सनसनीखेज दावा किया है।

उनके मुताबिक, बीजेपी में गए करीब 750 नेताओं ने औपचारिक रूप से कांग्रेस कार्यालय में वापसी के लिए आवेदन जमा किए हैं।

'उन्हें सिर्फ मुंबई में गड्ढे दिखते हैं उनका पूरा राज्य', राज ठाकरे ने प्रवासियों पर किया कटाक्ष

(जीएनएस)।

महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक बाद फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई में बसे प्रवासी लोगो पर जमकर कटाक्ष किया है। जबकि महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स को एक दिन पहले इएरळ कर्मचारी सहकारी ऋण समिति के चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के 24 घंटे बाद एक बार फिर राज ठाकरे ने प्रवासी लोगों को लेकर विवादित बयान दिया है।

21 अगस्त को मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा "जो लोग दूसरे राज्यों से मुंबई आते हैं" वे केवल शहर में गड्ढे देखते हैं। राज ठाकरे ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, "लेकिन वे यह नहीं देखते कि उनका पूरा राज्य ही एक गड्ढा है।"

उन्होंने ये बयान मुख्यमंत्री देवेंद्र

फडणवीस से दक्षिण मुंबई स्थित उनके आधिकारिक आवास पर हुई मुलाकात के बाद दिया। मनसे प्रमुख के अनुसार, यह बैठक मुंबई और अन्य शहरों से संबंधित नागरिक मुद्दों पर केंद्रित थी।

मनसे प्रमुख और भाजपा नेता के बीच यह मुलाकात ठाकरे चचेरे भाइयों, राज और उद्धव, को इएरळ कर्मचारी सहकारी ऋण समिति के चुनावों में हार का सामना करने के एक दिन बाद हुई। पिछले महीने उनके पुनर्मिलन के बाद यह पहला अवसर था जब उन्होंने एक साथ चुनाव लड़ा था। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और राज ठाकरे की मनसे के संयुक्त पैनल को इन चुनावों में 21 में से एक भी सीट नहीं मिली।

हालांकि, राज ठाकरे ने '' पर पोस्ट किया कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक "यातायात समस्याओं और पार्किंग मुद्दों" पर थी। उन्होंने कहा, "शहर बढ़ रहे हैं, नई परियोजनाएं आ रही हैं, और शहरों में लोगों का आना-जाना नहीं रुक रहा है। हम कबूतरों और हाथियों जैसे मुद्दों पर अटके हुए हैं, लेकिन हम पार्किंग जैसी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यातायात भीड़ सबसे गंभीर मुद्दा है, और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।"

उन्होंने बताया कि फडणवीस के समक्ष उन्होंने एक प्रस्तुति दी, जिसमें मुंबई पुलिस आयुक्त और संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) भी उपस्थित थे।

पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को मिली जान से मारने की धमकी, मैसेज में लिखा- 'बेटा तू तैयारी कर'

(जीएनएस)।

पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें फोन कॉल में ये धमकी दी गई है, जो एक विदेशी नंबर से कॉल और वॉट्सऐप मैसेज के जरिए दी गई है। औलख ने तुरंत इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। पुलिस ने तुरंत मामले में संज्ञान लेते हुए, जांच शुरू कर दी है। मनकीरत औलख फतेहाबाद, हरियाणा के रहने वाले हैं।

धमकी भरे मैसेज में लिखा, "तैयारी कर ले बेटे, तेरा टाइम आ गया, चाहे तू हो, तेरी पत्नी हो या चाहे तेरा बच्चा हो। हमे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बेटा अब तेरा नंबर लगाना है। इस धमकी को मजाक मत समझना। नंबर लगाना है बेटे, देख कैसे लगता है। अब तेरे साथ क्या-क्या होता है।"

धमकी से भरा ये मैसेज मनकीरत की मैनेजमेंट के आधिकारिक नंबर पर आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिंगर

को पहले एक वॉयस कॉल आई थी। ठीक इसके बाद ही धमकी भरा मैसेज आया है। हालांकि इस धमकी में किसी तरह की मांग नहीं की गई है। बता दें, ये पहली बार नहीं है जब मनकीरत को धमकी मिली है। करीब दो साल पहले भी ऐसा हो चुका है। तब उनकी गाड़ी का कई किलोमीटर तक बाइक सवार युवकों ने पीछा किया था। इसके बाद साल 2022 में जान से मारने की धमकी दी थी। तब इस मामले में गैंगस्टर दविंदर बंबीहा ग्रुप का नाम सामने आया था।

आपको जानकारी के लिए बता दें, पंजाबी सिंगर्स को धमकी वाले मामले साल 2018 से शुरू हुए हैं। तब मोहाली में पंजाबी गायक परमीश वर्मा पर हमला हुआ था। बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर गोलीबारी की थी। तब एक गोली उनके पैर में लगी। इस घटना को गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा ने अंजाम दिया था। पुलिस ने इसे चंडीगढ़ में गिरफ्तार कर लिया गया था।

सम्पादकीय

चुनाव आयोग पर विपक्ष का प्रहार

आखिर भारत के चुनाव आयोग ने चुनावी सवालों के मुद्दे पर प्रेस कांफ्रेंस की। प्रेस कांफ्रेंस तो की पर ज्वलंत सवालों के जवाबों को टालने पर ज्यादा जोर दिया गया। बेहतर होता कि चुनाव आयोग यह प्रेस कांफ्रेंस न करता। प्रेस कांफ्रेंस भी उस दिन की गई जब रविवार था और उसी दिन दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का रोड शो चल रहा था और बिहार के सासाराम में राहुल गांधी की वोट चोरी यात्रा आरंभ हो रही थी। नतीजा यह हुआ कि इस प्रेस कांफ्रेंस ने नए सवालों को जन्म दे दिया। लोकतंत्र में चुनाव केवल सरकार चलाने की वैधता हासिल करना नहीं, बल्कि यह उस चुनाव की बुनियाद का प्रमुख स्तंभ है, जिस पर देश, राज्य व लोकतंत्र का दारोमदार टिका हुआ है। इस प्रक्रिया के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से पारदर्शिता से संपन्न कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है। रविवार को चुनाव आयोग ने विपक्षी राजनीतिक दलों के वोट चोरी से जुड़े आरोपों के जवाब दिए। प्रेस कांफ्रेंस के बाद कांग्रेस ने कहा कि इस प्रेस कांफ्रेंस में विपक्ष के उठाए सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार चुनाव से ठीक पहले भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट देने का अधिकार छीन रही है। आरजेडी ने यह सवाल उठाया कि एसआईआर ऐसे समय क्यों की जा रही है जब बिहार में बाढ़ आई हुई है। पत्रकारों ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा था। इस पर आयोग ने कहा, बिहार में 2003 में भी एसआईआर हुआ था और उसकी तारीख भी 14 जुलाई से 14 अगस्त थी। तब भी यह सफलतापूर्वक हुआ था। राहुल गांधी ने दावा किया था कि 2004 के लोकसभा और महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनावों में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरपेर हुआ, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। विशेष रूप से, उन्होंने बेंगलुरु की महादेवपुरा विधानसभा में एक लाख से ज्यादा फर्जी वोटर और कई अमान्य पतों का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने डुप्लीकेट वोटरों (जैसे एक ही व्यक्ति का कई राज्यों में वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन) और गलत पतों (जैसे एक छोटे से कमरे में सैंकड़ों वोटर) के उदाहरण दिए थे। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को निराधार और गैर जिम्मेदाराना बताते हुए खारिज किया और कहा कि वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करोड़ों मतदाताओं, लाखों चुनाव कर्मचारियों की ईमानदारी पर हमला है। क्या राहुल गांधी के सवालों का यही जवाब था? राहुल गांधी बार-बार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग उनसे शपथ पत्र मांग रहा है, मुझसे एफीडेविट मांगा है जबकि वुछ दिन पहले ही भाजपा के लोग प्रेस कांफ्रेंस करते हैं तो उनसे कोई एफीडेविट नहीं मांगा जा रहा है। ज्ञानेश वुमार ने जवाब दिया, जहां आप गड़बड़ी की बात कर रहे हैं और आप उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नहीं हैं तो कानून के मुताबिक आपको शपथ पत्र देना होगा। आयोग का कहना है कि हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। अगर सात दिनों के अंदर हलफनामा नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि ये सभी आरोप निराधार हैं। पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग ने विपक्ष के सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया।

खेड़ा ने कहा क्या ज्ञानेश वुमार ने उन लाख वोटर्स के बारे में कोई जवाब दिया जिन्हें हमने महादेवापुरा में बेनकाब किया था? नहीं दिया। उन्होंने कहा, हमने उम्मीद की थी कि श्री ज्ञानेश कुमार हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे.. ऐसा लग रहा था कि (प्रेस कांफ्रेंस में) भाजपा का एक नेता बोल रहा है। वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता चुनाव आयोग की इस प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद थे। उनका मानना है कि फिलहाल जो सफाई चुनाव आयोग ने दी है उससे यह मुद्दा खत्म होते नहीं दिखाई दे रहा है। ठाकुरता कहते हैं, प्रेस कांफ्रेंस में वुछ सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं मिले है। जैसे मैंने पूछा कि क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में आपने 40 लाख नए लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल किया? इस पर आयोग ने कहा कि उस समय किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। मैंने एक और सवाल पूछा कि क्यों लोगों से ज्यादा नाम मतदाता सूची में थे तो इसका जवाब मुझे नहीं मिला। इस तरह से कई और सवाल हैं जिनके स्पष्ट जवाब नहीं मिले हैं। चुनाव आयोग ने बिहार ड्राफ्ट लिस्ट से करीब 65 लाख मतदाता हटाए हैं। यह एक बड़ी संख्या है, इसका कोई जवाब नहीं मिला।

उत्तर गुजरात की सहकारिता शक्तिः गाँव से वैश्विक बाजार तक डेयरी विकास की गाथा

- बनास डेयरी एशिया की अग्रणी डेयरी सहकारिताः ₹21,200 करोड़ कारोबार, 1 करोड़ लीटर प्रतिदिन प्रसंस्करण
- नवाचार और गुणवत्ता की मिसाल है दूधसागर डेयरीः ₹8,054 करोड़ कारोबार, 34.88 लाख लीटर प्रतिदिन संग्रह
- उत्तर गुजरात की डेयरी शक्ति का स्तंभ है साबर डेयरीः ₹8,939 करोड़ कारोबार, 33.53 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता
- प्रधानमंत्री मोदी के विजन से साकार हुआ उत्तर गुजरात का विश्वस्तरीय डेयरी सहकारिता मॉडल, VGRC में होगा प्रदर्शित

गांधीनगर, 21 अगस्त : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्राथमिक संकल्प रहा है कि देश के पशुपालक और किसान सशक्त हों, उन्हें न्यायसंगत मूल्य, आधुनिक सुविधाएँ और स्थायी आय का स्रोत मिले। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने यह दूरदृष्टि रखी थी कि डेयरी सहकारिता केवल दूध उत्पादन का माध्यम न होकर ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भरता का आधार बने, और आज मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल उसी संकल्प को नीतिगत प्रोत्साहन, अवसंरचना निवेश और निर्यात-उन्मुख योजनाओं के माध्यम से साकार कर रहे हैं।

इसी दृष्टिकोण का सजीव उदाहरण है उत्तर गुजरात का डेयरी क्षेत्र, जहाँ बनासकांठा, मेहसाणा और साबरकांठा की सहकारिताएँ अपनी प्रोसेसिंग क्षमता, कोल्ड-चेन अवसंरचना और नवाचार को अभूतपूर्व गति से बढ़ा रही हैं, जिससे उत्तर गुजरात ग्रामीण आजीविका और विकास की सशक्त अर्थव्यवस्था का प्रतीक बन चुका है। बनास डेयरी (बनासकांठा), दूधसागर डेयरी (मेहसाणा) और साबर डेयरी (साबरकांठा) दूध प्रसंस्करण और वैल्यू-ऐडेड उत्पादों के निर्यात में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी हैं, और ये सभी सहकारिताएँ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) के अंतर्गत 'अमूल' ब्रांड के तहत अपने उत्पादों का विपणन करती हैं।

बनास डेयरी एशिया की अग्रणी डेयरी सहकारिताः ₹21,200 करोड़ कारोबार, 1 करोड़ लीटर प्रतिदिन प्रसंस्करण

बनास डेयरी, एशिया की सबसे बड़ी डेयरी सहकारिताओं में से एक, 1969 में स्थापित हुई और इसका मुख्यालय गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर में स्थित है। वित्त वर्ष 2024-25 में ₹21,200 करोड़ से अधिक के कारोबार के साथ, यह सहकारिता भारत के डेयरी उद्योग में अग्रणी स्थान रखती है। 1 करोड़ लीटर से अधिक प्रतिदिन दूध प्रसंस्करण क्षमता और गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में फैली 20 अत्याधुनिक विनिर्माण इकाइयों के बल पर, बनास डेयरी ने विशाल भौगोलिक और परिचालन विस्तार हासिल किया है।

1,600 से अधिक दूध सहकारी समितियों और 4 लाख से अधिक किसानों की सहभागिता इसे ग्रामीण विकास और किसान सशक्तिकरण का मजबूत स्तंभ बनाती है। इसका उत्पाद पोर्टफोलियो पारंपरिक डेयरी उत्पादों से आगे बढ़कर शहद और खाद्य तेलों जैसे विविध उत्पादों को भी शामिल करता है। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के साथ बायोगैस संयंत्र में सफल सहयोग ने स्थिरता और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में इसकी प्रतिबद्धता को और सशक्त किया है।

नवाचार और गुणवत्ता की मिसाल है दूधसागर डेयरीः ₹8,054 करोड़ कारोबार, 34.88 लाख लीटर प्रतिदिन संग्रह

मेहसाणा जिला दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, जिसे व्यापक रूप से दूधसागर डेयरी के नाम से जाना जाता है, 1960 में स्थापित हुई और तब से मेहसाणा को डेयरी नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। वित्त वर्ष 2024झ25 में लगभग ₹8,054 करोड़ के कारोबार के साथ, यह सहकारिता अपनी उल्लेखनीय वृद्धि का प्रमाण देती है। मात्र 3,300 लीटर प्रतिदिन दूध संग्रह से शुरूआत कर, आज दूधसागर डेयरी प्रतिदिन 34.88 लाख लीटर से अधिक दूध का संग्रह और प्रसंस्करण कर रही है। मजबूत सहकारी नेटवर्क और उन्नत तकनीक के बल पर यह डेयरी दूध व विभिन्न डेयरी उत्पादों का उत्पादन करती है, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों बाजारों में उच्च गुणवत्ता के मानकों पर खरे उतरते हैं। अत्याधुनिक कोल्ड-चेन और सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली ने इसे निरंतर आपूर्ति, सुरक्षा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाए रखने में सक्षम बनाया है।

उत्तर गुजरात की डेयरी शक्ति का स्तंभ है साबर डेयरीः ₹8,939 करोड़ कारोबार, 33.53 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता

साबरकांठा जिला दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, जिसे व्यापक रूप से साबर डेयरी के नाम से जाना जाता है, प्रतिदिन 33.53 लाख लीटर दूध संभालने की क्षमता के साथ भारत के अग्रणी दूध प्रसंस्करण संस्थानों में से एक है। देश के कई राज्यों में फैले संचालन और वित्त वर्ष 2023झ24 में लगभग ₹8,939 करोड़ के कारोबार के साथ, साबर डेयरी ने दूध, घी, मक्खन और चीज जैसे उत्पादों में उत्कृष्ट गुणवत्ता और भरोसेमंद ब्रांड छवि स्थापित की है। ताजगी और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसने निरंतर अत्याधुनिक प्रसंस्करण संयंत्रों और मजबूत कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स में निवेश किया है, जिससे यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा के अग्रणी पायदान पर बनी हुई है।

VGRC में प्रदर्शित होगा उत्तर गुजरात का विश्वस्तरीय डेयरी सहकारिता मॉडल

बनास, दूधसागर और साबर डेयरी उत्तर गुजरात के डेयरी सहकारिता मॉडल की सशक्तता का प्रतीक हैं। न्यायसंगत मूल्य, सालभर दूध की खरीद और अवसंरचना विस्तार—जैसे कोल्ड-चेन, बायोगैस संयंत्र और मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में निवेश ने लाखों पशुपालकों की आजीविका को स्थायित्व दिया है।

'लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित करो', किसने की मांग?

(जीएनएस)।

कनाडा के कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोइलिएवरे ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है। यह मांग उन्होंने बुधवार को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक कार्यक्रम के दौरान उठाई। पोइलिएवरे ने अल्बर्टा के बैटल रिवर-क्रोफुट निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है और सितंबर में सदन के फिर से शुरू होने पर वे अपनी सीट पर लौटेंगे।

'लिबरल ने दी है बिश्नोई गैंग को छूट'

पोइलिएवरे ने इस मुद्दे को उठाने के लिए ट्विटर (अब एक्स) का भी सहारा लिया था। 11 अगस्त को, उन्होंने एक्स पर लिखा, "लिबरल ओपन बॉर्डर इमिग्रेशन ने बिश्नोई आतंकवादियों और गैंगस्टरों को कनाडा आने और हमारे समुदायों को आतंकित करने की अनुमति दी है। कंजर्वेटिव पार्टी की मांग हैः बिश्नोई आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाओ; उनके सभी सदस्यों को तुरंत गिरफ्तार करो और निर्वासित करो।"

बिश्नोई का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क

लॉरेंस बिश्नोई गिरोह एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क है, जो हिंसा, रंगदारी, मादक पदार्थों की तस्करी और लक्षित हत्याओं के लिए जिम्मेदार है, इसमें कनाडा में हुई वारदातें भी शामिल हैं। कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा जारी एक बयान में, पोइलिएवरे ने गिरोह को "एक आतंकवादी इकाई" के रूप में सूचीबद्ध करने की मांग की, ताकि पुलिस और अभियोजकों को "कनाडावासियों को धमकी देने वाले इस हिंसक, अंतरराष्ट्रीय रंगदारी नेटवर्क को खत्म करने के लिए मजबूत उपकरण" मिल सकें।

टूडो की सरकार में बढ़ा क्राइम

बयान में कहा गया है कि कनाडा में रंगदारी (ए७३ङ्ग१३ङ्गल्ल) "सबसे तेजी से बढ़ते अपराधों में से एक बन गया है", जिसमें पुलिस छोटे व्यवसाय मालिकों, खासकर ब्राम्पटन, सरे, वैंकूवर और कैलगरी जैसे समुदायों में, के खिलाफ खतरों की लहरों की रिपोर्ट कर रही है। बयान में आरोप लगाया

गया कि कनाडा में "अपराध और अराजकता" फैल रही है, और 2015 में प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो के नेतृत्व में लिबरल पार्टी के सत्ता में आने के बाद से "हिंसक अपराध में 54% की वृद्धि हुई है। यौन हमलों में 75% की वृद्धि हुई है। रंगदारी में 330% की वृद्धि हुई है।"

रंगदारों की बढ़े सजा

पार्टी ने सरकार से अनिवार्य जेल समय को बहाल करने और मजबूत करने के लिए कहा, ताकि रंगदारों को कम से कम तीन साल की सजा हो, अगर इसमें बंदूक शामिल हो तो चार साल, और संगठित अपराध से जुड़ा होने पर पांच साल की सजा हो, जिसमें आगजनी को सजा में एक गंभीर कारक माना जाए। उन्होंने सरकार से "कैच-एंड-रिलीज कानूनों" को रद्द करने और "हिंसक अपराधियों को सलाखों के पीछे रखने और घूमती हुई न्याय प्रणाली को समाप्त करने" की भी मांग की।

रंगदारों को टूडो ने दी शह-पोइलिएवरे

पोइलिएवरे ने कहा, "इस लिबरल सरकार ने कड़े कानूनों को ध्वस्त कर दिया, जेल की सजा को कम कर दिया, और गिरोहों तथा रंगदारों को हमारी सड़कों पर राज करने दिया।" यह पहली बार नहीं है कि पोइलिएवरे ने इस मुद्दे को उठाया है। इस बीच, कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गैरी आनंदसंगरी ने कहा है कि ऐसी पदनाम के लिए "कानूनी सीमा" को पूरा करना होगा, लेकिन मामला देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के विचाराधीन है।

'टारगेट किलिंग के लिए जिम्मेदार लॉरेंस'

कनाडा के अल्बर्टा प्रांत की नेता और ब्रिटिश कोलंबिया के उनके समकक्ष ने संघीय सरकार से ऐसी पदनाम के लिए जुलाई में आ'ान किया था। एक बयान में, अल्बर्टा के प्रीमियर डेनिएल स्मिथ और प्रांत के सार्वजनिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं के मंत्री माइक एलिस ने कहा था, "लॉरेंस बिश्नोई गिरोह एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क है, जो हिंसा, रंगदारी, मादक पदार्थों की तस्करी और लक्षित हत्याओं के लिए जिम्मेदार है, जिसमें कनाडा में भी शामिल हैं। इसकी पहुंच वैश्विक है, और इसका इरादा आपराधिक और हिंसक है।" बीसी प्रीमियर डेविड एब्बी ने भी जून में ओटावा से इसी तरह की बात कही थी।

गोल्डी बराड पर कार्रवाई की मांग

भारत ने भी कनाडा से संचालित बिश्नोई गिरोह के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसमें सतेंदरजीत सिंह, जिन्हें गोल्डी बराड़ के नाम से जाना जाता है, भी शामिल हैं। बराड़ मई 2022 में पंजाबी गायक और राजनेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के संबंध में वांछित है।

रोहित शर्मा हैं ड्रेसिंग रूम के असली बॉस, राहुल द्रविड़ ने हिटमैन को बताया सच्चा कप्तान

(जीएनएस)।

टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ ने हाल ही में रोहित शर्मा की कप्तानी की जमकर तारीफ की। आर अश्विन के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान द्रविड़ ने रोहित की लीडरशिप को लेकर कई अहम बातें शेयर कीं। उन्होंने कहा कि रोहित सिर्फ कप्तान नहीं थे, बल्कि एक ऐसे लीडर थे जो टीम के लिए जीते थे।

द्रविड़ ने बताया कि रोहित का सबसे बड़ा गुण था टीम के लिए गहरी सोच और साफ विजन। पूर्व कोच ने कहा कि पहले दिन से ही रोहित को पता था कि वह टीम को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। उन्हें यह भी पता था कि जीत के लिए किन चीजों पर फोकस करना जरूरी है। यह स्पष्टता ही उनके और रोहित के बीच मजबूत तालमेल का कारण बनी।

ड्रेसिंग रूम के माहौल को रखते थे पॉजिटिव

राहुल द्रविड़ ने कहा कि वह हमेशा मानते हैं कि कप्तानी करने वाले

कोच नहीं, बल्कि कप्तान होना चाहिए। द्रविड़ ने कहा कि मैंने हमेशा यही सोचा कि टीम को कप्तान के हिसाब से चलना चाहिए। कोच का काम उसे सपोर्ट करना है। रोहित के मामले में यह आसान था, क्योंकि वह अपनी बातों में स्पष्ट थे। उन्होंने आगे बताया कि रोहित न सिर्फ रणनीतिक रूप से मजबूत थे, बल्कि ड्रेसिंग रूम के माहौल को भी पॉजिटिव बनाए रखने पर जोर देते थे।

इस वजह से जीता वर्ल्ड कप

द्रविड़ ने आगे कहा कि रोहित ने शुरूआत से ही तय कर लिया था कि टीम का माहौल कैसा होना चाहिए। उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया, जिसमें खिलाड़ी खुलकर खेल सकें और दबाव महसूस न करें। राहुल द्रविड़ के मुताबिक, रोहित के पास वर्षों का अनुभव था, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। चाहे मुश्किल हालात हों या बड़े टूनार्मेंट, रोहित ने हमेशा संयम और स्पष्टता के साथ फैसले लिए।

यही वजह है कि उनकी कप्तानी में भारत ने जून 2024 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा। अंत में द्रविड़ ने कहा कि कप्तान का काम दिशा तय करना है और कोच को उसे सपोर्ट करना चाहिए। रोहित के साथ यह बेहद सहज था, क्योंकि वह जानते थे कि उन्हें टीम से क्या चाहिए।

कब है 'ब्लैक मून'? क्या चांद का रंग होगा काला? आने वाली है तबाही? जानें सारे सवालों का जवाब

(जीएनएस)।

अंतरिक्ष में हर वक्त कुछ ना कुछ घटता रहता है, जिसका पृथ्वी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कनेक्शन जरूर होता है इस बार भी आने वाले शनिवार यानी कि 23 अगस्त को कुछ ऐसा होने वाला है, जिस पर दुनियाभर के वैज्ञानिकों की नजर है, आपने सही समझा यहां बात हो रही है 'ब्लैक मून' की, जो कि इस महीने की 23 तारीख को आने वाला है।

खगोल विज्ञान की दृष्टि से 'ब्लैक मून' एक दुर्लभ खगोलीय घटना है, जो कि तब घटती है जब एक ही महीने में दो बार अमावस्या आती है। आमतौर पर एक महीने में केवल एक बार अमावस आती है लेकिन जब महीने में ये दो बार आए तो दूसरी अमावस्या को 'ब्लैक मून' कहा जाता है।

इ़ टङ्गङ्गल्ल 2025

वैसे खगोल विज्ञान में 'ब्लैक मून' कोई आधिकारिक शब्द नहीं है लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ खास तरह की चंद्र घटनाओं का वर्णन करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है जो अक्सर नहीं होती है।

चंद्र चक्र की तीसरी अमावस्या कहलाती है हर ऋतु में तीन अमावस्याएं होती हैं लेकिन कभी-कभी, चंद्र चक्र के हमारे कैलेंडर के साथ तालमेल बिठाने के कारण, चौथी अमावस्या भी आ जाती है। जब ऐसा होता है, तो क्रम में तीसरी अमावस्या को 'ब्लैक मून' कहा जाता है।

क्या चांद सफेद से काला हो जाएगा?

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों-उपग्रह की चाल का असर मनुष्य के सीधे जीवन पर पड़ता है इसलिए जब इनकी चालों पर अंतर या परिवर्तन होता है तो उसे अच्छा नहीं मानते हैं। अब यहां पर बात 'काले चांद' की हो रही है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उस दिन चांद सफेद से काला हो जाएगा। ये तो

'मौसमी मून' के हिसाब से उसका नाम रखा गया है। काले रंग को लोग शोक या दुख से जोड़ लेते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं 23 अगस्त को कुछ विनाशकारी या अशुभ होने जा रहा है, इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है।

अमावस्या के दिन चांद नजर नहीं आता है

दरअसल जिस दिन अमावस्या होती है, उस दिन चांद आकाश में नजर नहीं आता है। पंचांग के मुताबिक अमावस्या चंद्रमास के अंतिम दिन होती है। अमावस्या को अंधकार की रात भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन चांद पृथ्वी से काफी दूर होता है, जिसके कारण उसका चमकीला हिस्सा धरती से दिखाई ही नहीं पड़ता है।

चंद्रमा लगभग 29.5 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। जब किसी कैलेंडर माह में चंद्रमा का यह चक्र दो बार पूरा हो जाता है, तो उसी माह की दूसरी अमावस्या को 'ब्लैक मून 'कहा जाता है। ह घटना हर दो से तीन साल में एक बार घटित होती है।

'ब्लैक मून' को आत्मचिंतन, साधना और ध्यान के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है।

माना जाता है कि 'ब्लैक मून' का असर व्यक्ति की मानसिक स्थिति, भावनाओं और निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है।

नहीं बंद हुई सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान', इस एक्टर ने खोल दिए सारे राज

(जीएनएस)।

सलमान खान की आने वाली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग को लेकर खूब अपडेट आए। यहां तक बताया गया कि उनकी फिल्म ठंडे बस्ते में जा सकती है। बंद होने की खबरें भी आईं। लेकिन इन सबके बीच फैंस के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। 20 अगस्त को फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग शुरू हो गई है।

फिल्म की शूटिंग लद्दाख के इलाके में शुरू हुई है। इसकी जानकारी फिल्म में काम कर रहे एक्टर अंकुर भाटिया ने दी है। इंस्टाग्राम में अंकुर ने लद्दाख के मैदान की वीडियो पोस्ट की है। जिसमें कई सारी गाड़ियां आती दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी स्टोरी में उन्होंने बैटल ऑफ गलवान का क्लैप भी डाला है। जिसमें पहला दिन लिखा है।

लद्दाख में फिल्म का अहम पार्ट शूट होना था। इसके लिए सलमान खान ने कड़ी ट्रेनिंग भी ली है। लेकिन अभी वो इस शेड्यूल में जुड़े हैं कि नहीं। इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। फिल्म में सलमान खान-चित्रांगदा सिंह के अलावा अंकुर भाटिया और साकिब सलीम भी हैं। बीते दिनों बताया गया था कि सलमान की फिल्म 2020 में गलवान वैली में हुई उस हिंसक झड़प पर बेस्ड है। जिसमें भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों से लड़ाई हुई थी। एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि सलमान की फिल्म आर्मी की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है। ये मुद्दा काफी सेंसेटिव है। इसलिए ये फिल्म बंद भी सकती है। हालांकि सलमान आर्मी के अफसरों से बातचीत कर रहे हैं। दूसरी रिपोर्ट में ये बताया कि मुंबई के बांद्रा में फिल्म के लिए जो सेट लगाया गया था उसे तोड़ा जा रहा है। सेट तोड़ने की खबर सही है। लेकिन सेट इसलिए तोड़ा गया है क्योंकि मेकर्स अभी फिल्म की शूटिंग रियल लोकेशन पर करना चाहते हैं। ऐसे में स्टूडियो वाले सेट को तोड़ा है। अगर उन्हें जरूरत लगेगी, तो फिर से सेट बनाकर शूट करेंगे।

खैर फिल्म अगले साल मार्च या फरवरी में रिलीज हो सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो इस बार सलमान ईद का इंतजार नहीं करेंगे। हालांकि अभी तक फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट नहीं अनाउंस हुई है।

'भारत आज भी, सारे जहां से अच्छा', शुभांशु शुक्ला का एक्जोम-4 मिशन में जलवा, स्पेस में गूंजा 'जय हिंद'

(जीएनएस)।

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। कभी सीमित संसाधनों के साथ छोटे-छोटे प्रयोग करने वाला देश आज बड़े वैश्विक मिशनों में अपनी खास पहचान बना चुका है। इसरो की ऐतिहासिक उपलब्धियों से लेकर निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी तक, हर कदम भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में नई दिशा दे रहा है।

इसी कड़ी में एक्सिओम-4 मिशन भी एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, जिसमें भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर भारत का परचम लहराया और वैज्ञानिक प्रयोगों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

इसरो चेयरमैन वी. नारायणन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में साउथ एशिया सैटेलाइट तैयार कर लॉन्च किया गया और इसे दक्षिण एशियाई देशों को उपहार में दिया गया। इसके अलावा, जी20 देशों के लिए भी जी20 सैटेलाइट को साकार किया गया।

नरायणन ने आगे कहा कि दस साल पहले भारत में अंतरिक्ष से जुड़ा केवल एक स्टार्टअप था, लेकिन आज देश में 300 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप काम कर रहे हैं। निजी कंपनियां भी आगे बढ़ रही हैं और दो सबऑर्बिटल

मिशन पूरे कर चुकी हैं।

शुभांशु शुक्ला ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस

एक्सिओम-4 मिशन के मिशन पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने सरकार, इसरो और अपने सहयोगियों का आभार जताया। उन्होंने बताया कि इस मिशन में वे फाल्कन-9 रॉकेट पर सवार होकर क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष पहुंचे। उन्होंने कहा, "क्रू ड्रैगन दुनिया के उन तीन वाहनों में से एक है, जो इंसानों को अंतरिक्ष तक ले जा सकता है। मेरे पास मिशन पायलट की जिम्मेदारी थी, जहां मुझे कमांडर के साथ काम करते हुए क्रू ड्रैगन के सिस्टम से तालमेल बैठाना था।"

भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयोगों को दी सफलता

शुक्ला ने बताया कि मिशन के दौरान भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए कई प्रयोग सफलतापूर्वक पूरे किए गए। इसके अलावा, रळएट डेमो, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जैसे काम भी किए गए, जिससे भारत के शोध को नया आयाम मिला।

RNI No. GUJGUJ/2011/39228 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004, Ahmedabad,Gujarat-380 004. (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002 (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002. and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH

माननीय पीएम मोदी 25 अगस्त, 2025 को गुजरात दौरे पर आएँगे

कडी-साबरमती के बीच पहली मेमू ट्रेन और बेचराजी से कार-लोडेड मालगाड़ी का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 25 अगस्त, 2025 को गुजरात का दौरा करेंगे। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी दो महत्वपूर्ण नई रेल सेवाओं कडी और साबरमती के बीच पहली मेमू ट्रेन सेवा तथा बेचराजी से कार-लोडेड मालगाड़ी को अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे।

कलोल-कड़ी-कटोसन रोड मीटरगेज सेक्शन 15 सितंबर 2017 को ब्रॉड गेज में परिवर्तन हेतु बंद कर दिया गया था, जिस पर लगभग 8 साल के बाद पहली बार मीटर गेज से परिवर्तित ब्रॉडगेज लाइन पर कडी से साबरमती के बीच पहली मेमू ट्रेन की शुरूआत होने जा रही है जिससे अहमदाबाद, गांधीनगर और महेसाणा जिलों के रेल यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। यह ट्रेन सेवा दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों, कार्यालय जाने वालों और स्थानीय उद्यमियों के लिए तेज, सुरक्षित, विश्वसनीय और किफायती यात्रा कराएगी। अहमदाबाद (साबरमती) से कड़ी के बीच यह ट्रेन बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी, जहाँ वर्तमान में अहमदाबाद से कड़ी तक बस किराया ₹80 से ₹150 तथा टैक्सी भाड़ा ₹800 से ₹1200 के बीच है और यात्रा में 1 से 1.30 घंटे तक लगते हैं, वहीं यह नई ट्रेन सेवा यात्रियों का समय और धन दोनों बचाएगी।

साथ ही यह धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों तक पहुँच को सुगम बनाकर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को भी बढ़ाएगी। बेहतर यात्री संपर्क से स्थानीय व्यवसाय, व्यापारी और सेवा प्रदाता नए अवसरों से लाभान्वित होंगे, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

बेचराजी से कार-लोडेड मालगाड़ी की शुरूआत गुजरात के औद्योगिक परिदृश्य में नई ऊर्जा का संचार करेगी। ऑटोमोबाइल निर्माण और संबद्ध उद्योगों का प्रमुख केंद्र होने के कारण, बेचराजी को अब बेहतर लॉजिस्टिक समर्थन तथा राज्य और देश के अन्य हिस्सों तक सुदृढ़ कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। यह सेवा परिवहन लागत घटाएगी, आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क का विस्तार करेगी और माल की तेज आवाजाही सुनिश्चित करेगी। इससे न केवल ऑटोमोबाइल और विनिर्माण क्षेत्र का विकास होगा बल्कि नए रोजगार अवसर भी सृजित होंगे।

ये दोनों रेल सेवाएँ मिलकर गुजरात में स्थायी, पर्यावरण-अनुकूल और तेज गति वाले परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में योगदान देंगी। यात्रा समय में कमी, कनेक्टिविटी में सुधार और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के साथ ये पहल स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएंगी और दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक लाभ सुनिश्चित करेंगी।

भारतीय रेलवे की यह पहल क्षेत्रीय विकास को गति देने की प्रतिबद्धता को दशार्ती है और गुजरात की विकास यात्रा को नई दिशा प्रदान करेगी। साथ ही, यह 'विकसित भारत 2047' के राष्ट्रीय विजन में भी अहम योगदान देगी।

ताम्बरम-जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का अमलनेर स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव

मुंबई,

यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन संख्या 22663/22664 ताम्बरम-जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को प्रायोगिक आधार पर अमलनेर स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विवरण इस प्रकार है:-

23 अगस्त, 2025 को ताम्बरम से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22663 ताम्बरम-जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को अमलनेर स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया गया है। यह ट्रेन अमलनेर स्टेशन पर 14:45 बजे पहुँचेगी और 14:47 बजे प्रस्थान करेगी।

इसी प्रकार, 26 अगस्त, 2025 को जोधपुर से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22664 जोधपुर-ताम्बरम सुपरफास्ट एक्सप्रेस को अमलनेर स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया गया है। यह ट्रेन 16:16 बजे अमलनेर स्टेशन पहुंचेगी और 16:18 बजे प्रस्थान करेगी।

ट्रेनों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

सीएम गुप्ता पर हमले के बाद फटाफट दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त

(जीएनएस)।

दिल्ली में एक बड़े प्रशासनिक बदलाव के तहत, 1992 बैच के क्कर अधिकारी सतीश गोलचा को नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास पर जनसुनवाई के दौरान हुए हमले के ठीक एक दिन बाद, 21 अगस्त 2025 को की गई।

गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, 'सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, सतीश गोलचा, क्कर (AGMUT: 1992), जो वर्तमान में महानिदेशक (कारागार), दिल्ली के पद पर तैनात हैं, को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अगले आदेश तक दिल्ली के पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता है।' गोलचा, रइड सिंह का स्थान लेंगे, जिन्हें 1 अगस्त 2025 को दिल्ली पुलिस का कार्यवाहक कमिश्नर बनाया गया था।

20 अगस्त 2025 को सुबह करीब 8:15 बजे, सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान गुजरात के राजकोट से आए 41 वर्षीय राजेशभाई खिमजी भाई सकरिया ने उन पर हमला कर दिया। ऑटो चालक राजेश ने शिकायतकर्ता बनकर CM के आवास में प्रवेश किया और कथित तौर पर उन्हें धक्का दिया, बाल खींचे और थप्पड़ मारने की कोशिश की। मुख्यमंत्री की सुरक्षा टीम और वहां मौजूद लोगों ने उसे तुरंत पकड़ लिया।

उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास), 132 और 221 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस हमले ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गोलचा को नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया।

कौन हैं सतीश गोलचा?

सतीश गोलचा, 1992 बैच के AGMUT (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के IPS अधिकारी हैं, जिन्हें उनकी कठोर कार्यशैली और बेदाग छवि के लिए जाना जाता है। वर्तमान में वह महानिदेशक (कारागार), दिल्ली के पद पर तैनात थे, जिसका कार्यभार उन्होंने मई 2024 में संभाला था। गोलचा ने अपने करियर में दिल्ली पुलिस में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है, जिनमें पुलिस उपायुक्त (DCP), संयुक्त आयुक्त (Joint CP), विशेष आयुक्त (स्पेशल उढ) और स्पेशल CP (इंटेलिजेंस) शामिल हैं।

गोलचा ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान स्पेशल उढ (कानून और व्यवस्था, जोन-2) के रूप में अपनी सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया था। उन्होंने फरवरी 2022 से जून 2023 तक अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) के रूप में भी कार्य किया। दिल्ली पुलिस में उनकी पिछली भूमिकाओं में इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और आंतरिक सुरक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र शामिल रहे हैं, जिसके चलते उन्हें गंभीर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने का व्यापक अनुभव है। तिहाड़ जेल जैसे संवेदनशील कारागार का प्रबंधन करने का उनका अनुभव भी उनकी नियुक्ति के पक्ष में रहा।

रइड सिंह का छोटा कार्यकाल

सतीश गोलचा से पहले रइड सिंह, 1988 बैच के IPS अधिकारी, को 31 जुलाई 2025 को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। यह नियुक्ति तत्कालीन कमिश्नर संजय अरोड़ा के रिटायरमेंट के बाद की गई थी। हालांकि, रइड सिंह का कार्यकाल मात्र 21 दिन का रहा, जो दिल्ली पुलिस के इतिहास में सबसे छोटे कार्यकालों में से एक है। CM रेखा गुप्ता पर हमले के बाद उनकी सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्रालय ने उन्हें हटाकर गोलचा को स्थायी कमिश्नर नियुक्त किया।

क्यों महत्वपूर्ण है यह नियुक्ति?

दिल्ली, एक रणनीतिक और संवेदनशील महानगर होने के नाते, पुलिस कमिश्नर का पद न सिर्फ प्रशासनिक, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक संतुलन के लिहाज से भी अहम है। गोलचा की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब दिल्ली में + सुरक्षा के बावजूद मुख्यमंत्री पर हमला हुआ, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। गोलचा के सामने चुनौती होगी कि वह दिल्ली की कानून-व्यवस्था को मजबूत करें, खासकर संगठित अपराध, साइबर फ्रॉड, और आतंकी खतरों जैसे मुद्दों पर। उनकी तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में आपराधिक गिरोहों को नियंत्रित करने की क्षमता और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का अनुभव उन्हें इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाता है।

आगे की राह

सतीश गोलचा की नियुक्ति दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके सामने तिहाड़ जेल में बढ़ती हिंसा, आपराधिक गिरोहों की गतिविधियों, और साइबर अपराध जैसे मुद्दों से निपटने की चुनौती होगी। साथ ही, CM पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस की जवाबदेही और सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा भी जरूरी है। गोलचा की अनुभवी और शांत नेतृत्व शैली से दिल्लीवासियों को एक सुरक्षित और व्यवस्थित राजधानी की उम्मीद है। क्या यह नियुक्ति दिल्ली की कानून-व्यवस्था को नई दिशा देगी? आप क्या सोचते हैं?

14 सरकारी विधेयक पेश किए गए, 12 पारित हुए

(जीएनएस)।

21 अगस्त, 2025 (गुरुवार) को संसद के मानसून सत्र हंगामे के साथ संपन्न हो गया जैसा कि 21 जुलाई को शुरू हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए। विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन के बीच, ऑनलाइन गेमिंग विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित होने के बाद राज्यसभा को 10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा में मौजूद थे, जहां उनके आगमन पर सदन में जोरदार जयकारे लगे। इससे पहले, लोकसभा की कार्यवाही सुबह 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, जब विपक्ष ने बिहार में चुनावी सूचियों के पुनरीक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

41 घंटे 15 मिनट ही चला मानसून सत्र

मानसून सत्र केवल 41 घंटे 15 मिनट ही चला। सदन का कामकाज केवल 38.88 प्रतिशत रहा जो बहुत निराशाजनक है। उपसभापति हरिवंश ने बताया कि ने बताया कि लगातार गतिरोध के कारण सदन की कार्यवाही में व्यवधान आया। 'ऑपरेशन सिंदूर' पर चर्चा हुई, जिसमें 64 सदस्यों ने भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र की कार्यवाही समाप्त करते हुए विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शनों को सदन की कम उत्पादकता का कारण बताया। विपक्ष बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (रक्कक) पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा।

14 सरकारी विधेयक पेश किए गए, 12 पारित हुए

स्थगित करने से पहले, स्पीकर ने इस सत्र के दौरान हुए कामकाज की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सत्र में कुल 14 सरकारी विधेयक पेश किए गए, जिनमें से 12 पारित हुए। उन्होंने 28 और 29 जुलाई को 'ऑपरेशन सिंदूर' पर हुई विशेष चर्चा का भी जिक्र किया, जिसका समापन प्रधानमंत्री के जवाब के साथ हुआ।

केवल 55 प्रश्नों के ही मौखिक उत्तर दिए जा सके

स्पीकर ने 18 अगस्त 2025 को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर शुरू हुई विशेष चर्चा का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि सत्र में मौखिक उत्तर के लिए 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे, लेकिन केवल 55 प्रश्नों के ही मौखिक उत्तर दिए जा सके।

37 घंटे ही चर्चा हो पाई

बिरला ने कहा कि सत्र की शुरूआत में सभी ने सदन में 120 घंटे चर्चा करने का तय किया था, जिस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी सहमति बनी थी। हालांकि, नियोजित व्यवधान और लगातार गतिरोध के कारण केवल 37 घंटे ही चर्चा हो पाई।

सत्र के पहले ही दिन धनखड़ के इस्तीफा

सत्र के पहले ही दिन पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से मामला और बिगड़ गया, जिससे अटकलें तेज हो गईं और पद के लिए अप्रत्याशित चुनाव की आवश्यकता पड़ी। जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा, उनके पांच साल के कार्यकाल में दो साल शेष रहते हुए, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए, गहन अटकलों और षड्यंत्र सिद्धांतों को जन्म दिया। धनखड़ वीवी गिरी और आर वेंकटरमन के बाद अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले इस्तीफा देने वाले केवल तीसरे उपराष्ट्रपति हैं।

बिहार रक्कपर पूरे सत्र में जमकर हुआ हंगामा

विपक्ष ने चुनाव वाले बिहार में विशेष गहन संशोधन (रक्कक) पर कोई रियायत नहीं दिखाई। पहले दिन से ही पूरे सत्र के दौरान इंडिया गठबंधन का एसआईआर के खिलाफ संसद के अंदर और बाहर तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रखा, ईसीआई पर "वोट चोरी" का आरोप लगाया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, आप सांसद संजय सिंह ने जमकर रक्कक का विरोध किया। भाजपा विरोधी गुट ने "वोट चोरी बंद करो" लिखे बैनरों के साथ भी विरोध प्रदर्शन किया, और चल रहे मतदाता सूची के संशोधन को "साइलेंट इनविजिबल रिगिंग" बताया।

यशवंत वर्मा पर महाभियोग

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने "कैश-एट-होम" विवाद के संबंध में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। इस पैनल में कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता पीवी आचार्य एक न्यायविद् सदस्य के रूप में शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार और मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव समिति के अन्य सदस्य हैं।

लोकसभा में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन विधेयकों का एक सेट पेश किया, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और केंद्र तथा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में मंत्रियों के अनिवार्य इस्तीफे या निष्कासन का प्रावधान करता है, यदि वे पांच साल या उससे अधिक के कारावास के दंडनीय अपराधों के आरोप में 30 लगातार दिनों तक गिरफ्तारी या हिरासत में रहे हों।

हालांकि, ऐसा कुछ भी ऐसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों को हिरासत से रिहा होने पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा बाद में उसी पद पर नियुक्त होने से नहीं रोकेगा। संशोधनों का समय, संसद के मानसून सत्र के अंत से दो दिन पहले, और उनके निहितार्थों ने राजनीतिक हलकों को आश्चर्यचकित कर दिया।

ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक

संसद ने गुरुवार को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 पारित किया, जिसमें राज्यसभा ने हंगामे के बीच बिना बहस के इसे मंजूरी दी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पेश किया गया यह विधेयक ऑनलाइन मनी गेम्स के सभी रूपों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है, जबकि ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देता है।

विपक्ष के सदस्यों द्वारा लाए गए संशोधनों को खारिज करने के बाद ऊपरी सदन द्वारा इसे मंजूरी दी गई। यह विधेयक लोकसभा द्वारा बुधवार को पारित किया गया था। यह ऑनलाइन मनी गेम्स से संबंधित विज्ञापनों पर भी रोक लगाने और बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऐसे किसी भी खेल के लिए धन की सुविधा या हस्तांतरण करने से रोकने का प्रयास करता है। ऑनलाइन मनी गेम्स पैसे जमा करके खेले जाते हैं, जिसमें मौद्रिक और अन्य पुरस्कार जीतने की उम्मीद होती है।

शाहरुख खान के बेटे की सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में क्या होगा खास, दिग्गज स्टार करेंगे कैमियो

(जीएनएस)।

शाहरुख खान की बेटे की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' रिलीज होने के लिए तैयार है। इस सीरीज के साथ आर्यन खान अपना डिजिटल डेब्यू कर रहे हैं। उन्होंने इस सीरीज को लिखा और डायरेक्ट किया है। बीते दिनों इसका प्रीव्यू रिलीज किया गया। जिसके लॉन्च में शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान और 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की स्टारकास्ट भी मौजूद रही।

इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आर्यन खान की सीरीज आपको कब और कहां देखने को मिलेगी। इसके अलावा शो में कई बड़े स्टार्स की भी एंट्री होगी। कुछ का चेहरा हमने सीरीज के प्रीव्यू में देख लिया है।

आर्यन का यह शो नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर, 2025 को स्ट्रीम होगा। जिसमें लीड रोल में लक्ष्य ललवानी (किल फेम) आसमान सिंह के किरदार में नजर आएंगे। उनके अपोजिट सहेर बाम्बा होंगी, जो उनकी प्रेमिका का किरदार दिखाई देंगी। बॉबी देओल सुपरस्टार अजय तलवार की भूमिका में हैं। राघव जुयाल लक्ष्य के बेस्ट फ्रेंड बने हैं। इसके पहले दोनों किल में भी साथ में कर चुके हैं। वहीं, मोना सिंह उनकी मां के रोल में नजर आएंगी। इन सबके अलावा सीरीज में मनोज पाहवा, मनीष चौधरी, अन्या सिंह, गौतमी कपूर और राजत बेदी भी अहम रोल में दिखाई देंगे।

अब बात करते हैं शो में बॉलीवुड के जिन सुपरस्टार्स का कैमियो है। इसमें सलमान खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, करण जौहर जैसे सितारे इसमें नजर आएंगे। सारा अली और इब्राहिम के भी होने की खबरें हैं। सीरीज का सबसे बड़ा सरप्राइज यह है कि शाहरुख खान खुद भी आखिरी एपिसोड में नजर आएंगे।

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' एक ड्रामा सीरीज है। इसकी कहानी बॉलीवुड में आउटसाइडर और उसके दोस्तों के संघर्ष पर आधारित है। जो बॉलीवुड की चकाचौंध और राजनीति के बीच अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। इस सीरीज को "बॉलीवुड के लिए एक रोस्ट और टोस्ट" के रूप में बताया जा रहा है।

प्रेमी के घर से युवती की क्यों लगाई छलांग, जानिए पूरा मामला, धोखे और मारपीट की दर्दनाक कहानी

(जीएनएस)।

खरगोन की रहने वाली 24 वर्षीय युवती (नाम गोपनीय) बुधवार रात, 20 अगस्त 2025 को अपने प्रेमी आवेश खान के घर इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में पहुंची।

सूत्रों के अनुसार, युवती और आवेश पिछले कुछ सालों से रिलेशनशिप में थे। लेकिन हाल ही में युवती को पता चला कि आवेश ने किसी दूसरी युवती से शादी कर ली है। इस बात से आहत और गुस्से में भरी युवती ने आवेश से जवाब मांगने के लिए उसके घर का रुख किया।

कहासुनी और मारपीट का दौर

युवती के मुताबिक, आवेश के घर पहुंचने पर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। युवती ने आवेश पर धोखा देने और दूसरी शादी करने का आरोप लगाया। बात इतनी बढ़ गई कि आवेश ने गुस्से में युवती का मुंह दबाकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पुलिस को दिए बयान में युवती ने बताया कि आवेश ने उसे थप्पड़ मारे और उसका गला दबाने की कोशिश की। इस दौरान घर में मौजूद आवेश की दूसरी पत्नी को देखकर युवती का गुस्सा और भड़क गया। उसने हंगामा शुरू कर दिया और आवेश को सबक सिखाने का मन बना लिया।

हंगामे के बीच युवती ने आवेश का हाथ पकड़ा और उसे जबरन घर की तीसरी मंजिल की छत पर ले गई। गुस्से और आवेश में भरी युवती ने वहां से छलांग लगा दी। यह दृश्य दिल दहलाने वाला था। लेकिन छलांग लगाने के दौरान वह पास की बिजली की तारों में उलझ गई, जिसके कारण उसकी जान बच गई। हालांकि, इस हादसे में उसके हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवती का शरीर तारों में कुछ देर तक लटका रहा, जिसके बाद वह नीचे गिर गई।

घटना के तुरंत बाद आवेश और उसके परिवार ने युवती को पास के अर्पण अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही परिवार वहां से भाग निकला। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आवेश ने इस दौरान युवती के मोबाइल से कुछ चैट्स और अन्य डेटा डिलीट करने की कोशिश की, ताकि सबूत मिटाए जा सकें। अस्पताल में मौजूद बजरंग दल के कार्यकताओं को इस घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद वे भी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया।

सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत जांच शुरू कर दी। घटना का एक वीडियो, जो पास के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था, गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

यूपीआई 3.0 खत्म करेगा कैश और फोन का झंझट ! जानें क्यों खास है यह अपग्रेड और कैसे बदल देगा आपकी लाइफस्टाइल?

(जीएनएस)।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) देश की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था में एक और बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है। ठढउक जल्द ही वढक 3.0 पेश करने जा रहा है, जो Internet of Things (IoT) तकनीक पर आधारित होगा।

इस अपग्रेड के बाद न सिर्फ स्मार्टफोन बल्कि आपके घर और कार में मौजूद स्मार्ट डिवाइस भी अपने आप पेमेंट करने लगेंगे। इसका मतलब है कि अब आपकी कार, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन या स्मार्टवॉच जैसे उपकरण खुद-ब-खुद बिल चुकाने और खरीदारी करने में सक्षम होंगे।

कैसे करेगा काम UPI 3.0?

UPI 3.0 मौजूदा फीचर्स जैसे UPI Autopay और UPI Circle पर आधारित होगा। इसमें IoT तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके जरिए इंटरनेट से जुड़े सेंसर और सॉफ्टवेयर अलग-अलग डिवाइसों को एक-दूसरे से जोड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर:

आपका फ्रिज दूध खत्म होने पर खुद ऑर्डर और पेमेंट कर देगा।

आपकी कार ईंधन भरवाने के तुरंत बाद भुगतान पूरा कर देगी।

स्मार्ट टीवी या स्मार्टवॉच से मासिक सब्सक्रिप्शन अपने आप कट जाएगा।

इस सुविधा के लिए यूजर अपने मुख्य वढक डिवाइस से किसी स्मार्ट डिवाइस को एक मैंडेट जारी करेंगे। इससे एक सेकेंडरी वढक कऊ बनेगी, जो आपके मुख्य खाते से जुड़ी होगी और निर्धारित सीमा के भीतर ही लेनदेन कर पाएगी।

अब UPI पेमेंट के लिए नहीं चाहिए PIN! बस करना होगा इतना सा काम, जानिए नया बायोमेट्रिक प्लान

अब वढक पेमेंट के लिए नहीं चाहिए ढक्क! बस करना होगा इतना सा काम, जानिए नया बायोमेट्रिक प्लान

UPI 3.0 Smart Device: सुरक्षा और प्राइवेसी

सूत्रों के मुताबिक, इस क्रांतिकारी अपग्रेड की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2025 में मुंबई में होने वाले Global Fintech Fest के दौरान की जा सकती है। हालांकि, इसके लिए अभी नियामकीय मंजूरी का इंतजार है।

NPCI ने स्पष्ट किया है कि डेटा सुरक्षा और अनधिकृत लेनदेन से बचाव के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। हर डिवाइस के लिए अलग वढक कऊ होगी, जिससे किसी एक डिवाइस के डेटा से पूरा अकाउंट असुरक्षित नहीं होगा।

UPI 3.0 आखिर क्यों है खास?

भारत में वढक का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में UPI के जरिए 185.8 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए, जो पिछले साल से 41.7% अधिक है। फ्हक की रिपोर्ट बताती है कि देश में खुदरा भुगतानों का 83% हिस्सा UPI से किया जा रहा है। वहीं, वैश्विक स्तर पर भी ऑटोनॉमस पेमेंट्स मार्केट 2024 से 2032 के बीच 40% से अधिक की दर से बढ़ने का अनुमान है।

UPI 3.0 न केवल पेमेंट को और आसान बनाएगा, बल्कि इसे भविष्य की ऑटोमेटेड डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा भी बना देगा। आने वाले समय में यह अपग्रेड हमारे रोजमर्रा के जीवन को बदल देगा, जहां डिवाइस खुद हमारी जरूरतें पूरी करेंगे और पेमेंट भी बिना देरी के हो जाएगा।

पश्चिम रेलवे - अहमदाबाद मण्डल

ई-निविदा सूचना संख्या : Sr.DEE/TR/ADI/18(2025-26) दिनांक : 20.08.2025

रिमोट कंट्रोल (टीपीसी) के माध्यम से लूप लाइन और यार्ड लाइनों को मुख्य लाइन से अलग करने की सुविधा सहित सेक्शनिंग सुधार

निविदा सं. TRD-ADI-T-06R2-2025-26

कार्य का नाम: अहमदाबाद मण्डल :- रिमोट कंट्रोल (टीपीसी) के माध्यम से लूप लाइन और यार्ड लाइनों को मुख्य लाइन से अलग करने की सुविधा के साथ अहमदाबाद मण्डल के विभिन्न स्टेशनों पर सेक्शनिंग सुधार।

अनुमानित लागत: ₹12,89,61,182.50 | **बयाना राशि:** ₹ 7,94,800/-

निविदा जमा करने एवं खुलने की तिथि एवं समय: दिनांक: 17.09.2025 को 15:00 बजे उसके बाद नहिं एवं दिनांक: 17.09.2025 को 15:30 बजे निविदा खोली जायेगी।

कार्यालय का पता एवं वेबसाईट विवरण: वरिष्ठ मण्डल बिजली अभियंता, म.रे.प्र. कार्यालय (प.रे.), चामुंडा पुल के पास, जी.सी.एस. अस्पताल के सामने, नरोडा रोड़, अमदुपुरा, अहमदाबाद-382345

वेब साईट का पता: www.ireps.gov.in ADI-141

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: x.com/WesternRly

पश्चिम रेल्वे

विभिन्न कार्य

मंडल रेल प्रबंधन (पश्चिम रेलवे), पश्चिम रेलवे, छठी मंजिल, इंजीनियरिंग विभाग, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400008. निविदा सूचना संख्या. BCT/25-26/187 दिनांक 18.08.2025 क्रमांक 1 आमंत्रित करता है। कार्य और स्थान: उधना - जलगाँव - TBSR (H Beam) - उधना - उकाई - सोनगढ़ - TBR -12.218 TKM और उधना-जलगाँव-TBSR (H-Beam) के संबंध में 138 नंग. 138 नंग और ट्रैकमैनों के लिए टूल रूम सह विश्राम कक्ष. कार्य की अनुमानित लागत: रु. 60,77,856.23/- ईएमडी: रु. 1, 21,600.00/- क्रमांक 2: निविदा सूचना संख्या BCT/25-26/188 दिनांक 18.08.2025 कार्य और स्थान: उधना-उकाई सोनगढ सेक्शन। पुल संख्या 60 ADEN - VYARA सेक्शन में अतिरिक्त जल मार्ग प्रदान करना। कार्य की अनुमानित लागत: रु. 2,64,07,307.03/- ईएमडी: रु. 2,82,000.00/ दोनों निविदाएं जमा करने की तिथि और समय: दिनांक 16.09.2025, 15.00 बजे तक। दोनों निविदाएं खोलने की तिथि और समय: दिनांक 16.09.2025 को 15.30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें: www.ireps.gov.in 0514

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly

जीएआरसी की चौथी रिपोर्ट में राज्य में विकेन्द्रित योजना व्यवस्था को अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधित्व आधारित तथा जनकेन्द्रित बनाने की सिफारिशें

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट सौंपी गई

राज्य के योजना ढाँचे में मूलभूत परिवर्तन लाकर नागरिकों को सीधा ही लाभ पहुँचाने वाली सिफारिशें

-: जीएआरसी के अध्यक्ष डॉ. हसमुख अढिया के दिशादर्शन में आयोग की चौथी रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें :-

- जिला योजना बजट में आगामी पाँच वर्ष में सात से आठ गुना वृद्धि
- जिला योजना समिति में निर्वाचित प्रतिनिधियों का बहुमत झ जिले के प्रभारी मंत्री समिति के अध्यक्ष
- योजना के लिए फिक्स कैलेंडर
- तहसील स्तर पर एकीकृत समिति
- विलेज डेवलपमेंट प्लान झ नागरिकों की विकास कार्यों में सीधी भागीदारी

चौथी रिपोर्ट की सिफारिशें जीएआरसी की वेबसाइट पर उपलब्ध

गांधीनगर, 21 अगस्त :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए विकसित भारत@2047 के संकल्प में विकसित गुजरात@2047 को अग्रसर रखने के ध्येय से राज्य शासन के प्रशासनिक ढाँचे एवं कार्यपद्धति में आवश्यक फेरबदल के लिए मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया की अध्यक्षता में गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग (जीएआरसी) का गठन किया है।

इस संदर्भ में; जीएआरसी द्वारा अब तक राज्य सरकार को तीन सिफारिश रिपोर्ट सौंपी गई हैं और उसकी कुल 25 सिफारिशें क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

जीएआरआरसी के अध्यक्ष डॉ. हसमुख अढिया के दिशादर्शन में लगभग 9 सिफारिशों के साथ तैयार की गई चौथी सिफारिश रिपोर्ट गुरुवार को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को सौंपी गई।

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2024 में राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस पर संकल्प किया था, 'हमारी सरकार पंचायतीराज संस्थाओं को मजबूत बनाने तथा लोगों के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर कार्यरत रहेगी।' प्रधानमंत्री के इस संकल्प को गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गाँव से राज्य तक लोकतंत्र आधारित विकास मॉडल से साकार करने के उद्देश्य से जीएआरसी की इस चौथी सिफारिश रिपोर्ट में विकेन्द्रित योजना संबंधी सिफारिशें की गई हैं।

इस चौथी रिपोर्ट में विकेन्द्रित योजना तथा बजट व्यवस्था के संबंध में जो ऐतिहासिक सिफारिशें की गई हैं, उनके परिणामस्वरूप अपेक्षा व्यक्त की गई है कि इन सिफारिशों से लोककेन्द्रित विकास, पारदर्शिता तथा जिम्मेदारी के नए युग की शुरूआत होगी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य

में गाँव से तहसील एवं जिले की योजना प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधित्व आधारित तथा जनकेन्द्रित बनेगी।

मुख्यमंत्री को जीएआरसी की यह चौथी रिपोर्ट आयोग के अध्यक्ष डॉ. हसमुख अढिया द्वारा सौंपे जाने के अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री एस. एस. राठौड़, प्रशासनिक सुधार प्रभाग के प्रधान सचिव श्री हारित शुक्ला, मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. विक्रांत पांडे तथा योजना प्रभाग की सचिव श्रीमती आर्द्रा अग्रवाल एवं जीएआरसी के अधिकारी उपस्थित रहे।

जीएआरसी की इस चौथी रिपोर्ट में गुजरात के योजना ढाँचे में मूलभूत परिवर्तन लाने वाली सिफारिशें की गई हैं, जो राज्य के नागरिकों को सीधा लाभ पहुँचाने वाली हैं। इन सिफारिशों द्वारा राज्य में विकेन्द्रित योजना को मजबूत बनाने एवं गाँवों को विकास प्रक्रिया के केन्द्र में लाने का महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

इस रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों में जिला योजना के बजट में आगामी पाँच वर्ष में लगभग सात से आठ गुना भारी वृद्धि, जिला योजना मंडल के स्थान पर जिला योजना समिति झ निर्वाचित प्रतिनिधियों को बहुमत, योजना के लिए फिक्स कैलेंडर, तहसील स्तर पर एकीकृत समिति तथा विलेज डेवलपमेंट प्लान का समावेश होता है।

जिला योजना के बजट में आगामी पाँच वर्ष में लगभग सात से आठ गुना भारी वृद्धि

स्थानीय स्तर के बुनियादी कड़ीरूपी कार्यों के लिए जिला योजना का जो बजट वर्षों से स्थिर रहा है, उसमें अब आयोग द्वारा आगामी पाँच वर्षों में वार्षिक 10,000 करोड़ रुपए की भारी राशि की वृद्धि करने की सिफारिश की गई है। बजट की वृद्धि होने से अधिक सड़क मार्ग, अधिक स्कूल, अधिक स्वास्थ्य सुविधाएँ और अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे तथा ग्रामीण स्तर के जमीन से जुड़े लोगों की शासन में भागीदारी बढ़ेगी।

जिला योजना मंडल के स्थान पर जिला योजना समिति झ निर्वाचित प्रतिनिधियों को बहुमत

राज्य में 1973 से जिला स्तरीय योजना के लिए जिला योजना मंडल अस्तित्व में हैं। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि इस जिला योजना मंडल के स्थान पर जिला स्तरीय तमाम योजनाओं की मंजूरी अब से भारत के संविधान में दिए गए सुझाव के अनुसार जिला योजना समिति द्वारा दी जाए।

इतना ही नहीं; जिला योजना समिति में जिला स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्राथमिकता देकर पंचायत स्तर को अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा तथा जिला योजना समिति में जिले के प्रभारी मंत्री अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। अब जिला स्तर पर योजनाएँ निर्धारित करने का अधिकार जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में आएगा और लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ भी साकार हो सकेगा।

योजना के लिए फिक्स कैलेंडर

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यों को तय करने से लेकर प्रशासनिक मंजूरी व टेंडरिंग तथा वर्क ऑर्डर जारी करने के लिए आयोग द्वारा एक फिक्स कैलेंडर की सिफारिश की गई है। इस कैलेंडर के अनुसार आगामी वर्ष की योजना प्रक्रिया इस वर्ष के जून-जुलाई माह से ग्रामीण स्तर पर शुरू होगी और ये सारी प्रशासनिक प्रक्रियाएँ इस प्रकार पूरी की जाएंगी कि आगामी वर्ष के अप्रैल माह से वास्तव में कामकाज शुरू हो सके तथा समयसीमा में कार्य पूरे हो सकें। इस प्रकार के कैलेंडर से योजना एवं क्रियान्वयन निर्धारित समयसीमा में पूर्ण हो सकेंगे एवं धन का श्रेष्ठ उपयोग व गुणवत्तायुक्त कार्य होंगे।

तहसील स्तर पर एकीकृत समिति

तहसील स्तर पर योजना मंजूर करने के लिए मौजूदा स्थिति में एक से अधिक समितियाँ अस्तित्व में हैं। इनमें सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यों को मंजूरी दी जाती है, परंतु इन अलग-अलग समितियों के कारण तहसील स्तर पर कई बार समन्वय के अभाव के चलते अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

अब आयोग द्वारा तहसील स्तर पर किसी भी कार्य की मंजूरी के लिए एक ही समिति 'एकीकृत तहसील योजना' समिति रखने की सिफारिश की गई है। इससे कार्य मंजूर होने में विलंब को रोका जा सकेगा तथा उलझन-दुविधा भी कम होगी। तहसील स्तर पर तेज एवं एकीकृत निर्णय लिए जाने से हर नागरिक को उसका सीधा लाभ भी मिलेगा।

विलेज डेवलपमेंट प्लान झ नागरिकों की सीधी भागीदारी

हर गाँव स्वयं विलेज डेवलपमेंट प्लान तैयार करेगा और ग्रामसभा द्वारा इस विलेज डेवलपमेंट प्लान को मंजूर किया जाएगा। तहसील एवं जिला स्तर पर जिन कार्यों की योजना मंजूर की जाएगी, उन सभी योजनाओं के लिए कार्यों का चयन इस विलेज डेवलपमेंट प्लान से ही करना होगा।

अब ग्रामीणजन स्वयं तय करेंगे कि उनके क्षेत्र में कौन-से कार्य होने चाहिए। इस प्रकार; ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग भी अब विकास में भागीदार बनेंगे तथा गांधीजी की स्वराज की कल्पना 'गाँव अपना भविष्य स्वयं तय करे' सही अर्थ में साकार होगी। इसके अतिरिक्त; ग्रामीण स्तर पर शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य केन्द्र जैसी प्राथमिक सुविधाओं के लिए लोग स्वयं ही प्राथमिकताएँ तय कर सकेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को यह विचार दिया है कि विकास के सच्चे सशक्तिकरण के लिए गाँव स्वयं अपने निर्णय लें और अपने विकास में स्वयं ही भागीदार बनें। प्रधानमंत्री के इस विचार के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में विकसित भारत@2047 में ग्रामीण क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाकर विकसित गुजरात@2047 का सपना साकार करने में जीएआरसी की इस चौथी रिपोर्ट की सिफारिशें मजबूत नींव प्रदान करेंगी और गाँव से तहसील व जिले में लोककेन्द्रित योजना राज्य के प्रशासन को अधिक प्रभावी एवं जिम्मेदार बनाएंगी।

राज्य में विकेन्द्रित योजना व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए जीएआरसी की चौथी रिपोर्ट में जो अन्य सिफारिशें की गई हैं; उनमें एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट से इतर सामान्य प्रशासन विभाग (योजना) के अधीनस्थ सभी योजनाओं के कार्यों के चयन के लिए अब एक ही प्रक्रिया का अनुकरण करने, टेक्नोलॉजी आधारित ट्रैकिंग सिस्टम, विकासशील तहसील के मानदंड नएसिरे से तय करने और परफॉर्मेंस आधारित जिम्मेदारी आदि सिफारिशें शामिल हैं।

जल्द होगा रूस-यूक्रेन युद्ध पर फैसला! ट्रंप से मुलाकात के बाद अब मैक्रों ने पीएम मोदी को लगाया फोन, किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से फोन पर वार्ता की जिसमें यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ हुई इस बातचीत को पीएम मोदी ने बहुत अच्छी बताया। रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों पर भी बात हुई।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से फोन पर बातचीत की। बातचीत की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स हैंडल पर लिखा,"मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता दोहराई।"

बता दें कि रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन, वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय यूनियन के नेताओं से बातचीत की। अलास्का में पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की से बात की। ट्रंप ने उम्मीद जताया है कि जल्द ही तीनों नेता एक साथ बैठकर युद्ध की समाप्ति पर फैसला लेंगे।

'कांग्रेस के युवा नेता काबिल', पीएम मोदी का ये बयान राहुल गांधी को कर सकता है 'परेशान', जो कहा वो आप भी पढ़ें

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए नेताओं के साथ हुई 'टी मीटिंग' में विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर करारा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस में कई युवा और बेहद प्रतिभाशाली नेता हैं, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि "परिवार की असुरक्षा" हावी रहती है। उनका इशारा साफ तौर पर राहुल गांधी की ओर था।

उन्होंने कहा कि इन युवा नेताओं की मौजूदगी राहुल गांधी को असुरक्षित और बेचैन महसूस कराती है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कहा कि 'कांग्रेस के युवा नेता काबिल हैं, लेकिन राहुल गांधी इनको लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के युवा नेताओं से घबराए हुए हैं।

'बैठक में नहीं था कोई विपक्ष का नेता मौजूद'

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर युवा नेताओं को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया है। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में केवल एनडीए के नेता मौजूद थे, विपक्ष से कोई नहीं आया था। सोशल मीडिया पर भी स्पीकर की चाय पार्टी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नहीं पहुंचने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अब लोग लिख रहे हैं कि पीएम मोदी का ये बयान राहुल गांधी को परेशान कर सकता है।

पीएम मोदी ने हाल ही में संपन्न हुए संसद सत्र को सफल बताया और कहा कि इस दौरान कई अहम बिल पास हुए। उन्होंने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग बिल का जिक्र किया और इसे "जनता से सीधे जुड़े दूरगामी प्रभाव वाला सुधार" बताया।

पीएम मोदी का विपक्ष पर सीधा वार

पीएम मोदी ने विपक्ष को संसद में गैर-जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष गंभीर मुद्दों पर चर्चा से बचता है और केवल व्यवधान डालता है। यहां तक कि जब गृह मंत्री अमित शाह ने तीन बड़े बिल पेश किए, तो विपक्षी सांसदों ने उसकी कॉपियां फाड़कर सदन में हंगामा किया।

सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने संसद में महत्वपूर्ण विधेयकों पर बहस से किनारा कर लिया और सिर्फ हंगामा खड़ा करने में समय बिताया। पीएम मोदी ने यह भी इशारा किया कि विपक्ष में, खासकर कांग्रेस पार्टी में, कई युवा नेता बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उन्हें आगे आने और अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता। उनका मानना है कि राहुल गांधी इन नेताओं की बढ़ती लोकप्रियता से असुरक्षित महसूस करते हैं और इसी वजह से उन्हें मंच नहीं मिलता।

गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने पत्रकार अभिसार शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, वीडियो में सरकारों की आलोचना का आरोप

गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने पत्रकार अभिसार शर्मा के खिलाफ एक वीडियो में कथित तौर पर असम और केंद्र सरकारों की आलोचना करने पर एफआईआर दर्ज की है। शिकायत में सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता पर चिंता जताई गई है।

गुवाहाटी, 21 अगस्तः गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने पत्रकार और यूट्यूबर अभिसार शर्मा के खिलाफ एक प्राथमिकी (ऋक्षफ) दर्ज की है। यह कार्रवाई एक शिकायत के आधार पर की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि शर्मा ने एक ऐसा वीडियो अपलोड किया जिसमें असम सरकार और केंद्र सरकार की कथित रूप से आलोचना की गई है।

यह FIR गुरुवार को दर्ज की गई, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 152, 196 और 197 का उल्लेख किया गया है। ये धाराएं राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डालने, समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बयान देने से संबंधित हैं। शिकायतकर्ता आलोक बरुआ, जो नयनपुर, गणेशगुरी का 23 वर्षीय निवासी है, ने आरोप लगाया कि शर्मा के वीडियो में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। वीडियो में 'राम राज्य' की अवधारणा का भी कथित रूप से मजाक उड़ाया गया और यह दावा किया गया कि सरकार "हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण पर ही टिकी हुई है।"

बरुआ ने आरोप लगाया कि ये टिप्पणियां जानबूझकर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को बदनाम करने और सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के इरादे से की गई थीं। उन्होंने यह भी कहा कि वीडियो के कारण उनके इलाके में चर्चा शुरू हो गई है और धर्म आधारित विभाजन की आशंका जताई जा रही है, जिससे सार्वजनिक शांति और सौहार्द प्रभावित हो सकता है। FIR में यह भी उल्लेख किया गया है कि शर्मा की टिप्पणियां लोगों की भावनाएं भड़का सकती हैं, वैध प्राधिकरणों पर विश्वास को कमजोर कर सकती हैं और धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा दे सकती हैं।

भारतीय न्याय संहिता के तहत, धारा 152 अब रद्द की गई देशद्रोह कानून की जगह लेती है और भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध मानती है। धारा 196 धर्म और जाति के आधार पर वैमनस्य फैलाने को संबोधित करती है, जबकि धारा 197 राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने वाले बयानों से संबंधित है।

खत्म हुआ ऋतिक रोशन की 14 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म वॉर 2 का क्रेज, 200 करोड़ कमाना हुआ मुश्किल

सिनेमाघरों में 14 अगस्त को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसने अपना पहला हफ्ता यानी 7 दिन पूरे कर लिए हैं। सोमवार से ही फिल्म के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिल रही है। सातवें दिन फिल्म का कलेक्शन और गिर गया है। फिल्म का कुल कलेक्शन 199 करोड़ रुपये हो गया है। लेकिन दिन के हिसाब से इसकी कमाई गिरती जा रही है।

सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने सातवें दिन 5.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसके पहले छठवें दिन 8.25 करोड़ रुपये, पांचवें दिन 8.75 करोड़ रुपये, चौथे दिन 31 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 33 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 56.50 करोड़ रुपये और पहले दिन 51.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। ऐसे में

फिल्म का कुल कलेक्शन 199 करोड़ रुपये पहुंच गया है। दिन प्रतिदिन फिल्म की ऑक्यूपेंसी भी गिर रही है।

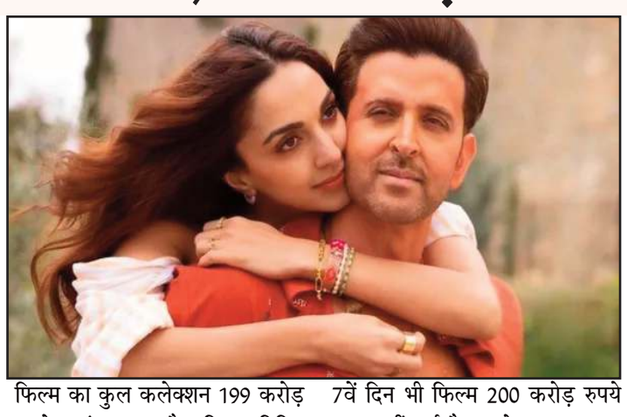

इस फिल्म की गिरती कमाई से मेकर्स खुश नहीं है। क्योंकि फिल्म की शुरूआती कमाई देख, उन्हें लगा था कि आसानी से 200 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो जाएगी। लेकिन 7वें दिन भी फिल्म 200 करोड़ रुपये कमा नहीं पाई है। इसके अलावा अब फिल्म के ओटीटी पर भी रिलीज होने की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म वॉर 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इस फिल्म को ओटीटी पर आने में करीब 8 हफ्तों का समय लगेगा। थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए इतने दिनों का विंडो होता है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है कि वॉर 2 किस प्लेटफॉर्म पर आएगी।

'वॉर 2' में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के साथ कियारा आडवाणी भी मुख्य भूमिका में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म का निर्माण ₹400 करोड़ के भारी-भरकम बजट में हुआ है। फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ जूनियर एनटीआर को कास्ट किया। इसके जरिए वो नॉर्थ और साउथ दोनों ही इंडस्ट्री के दर्शकों को साधना चाहते हैं। हालांकि इस मामले में मेकर्स का क्या प्लान बहुत सक्सेसफुल होता नजर नहीं दिख रहा है। इस फिल्म को भी ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है।

मोहन के नेतृत्व में मध्यप्रदेश बनेगा देश की 'माइनिंग कैपिटल', कटनी में 23 अगस्त को माइनिंग कॉन्क्लेव

(जीएनएस)।

मध्य प्रदेश खनन क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बन रहा है, महत्वपूर्ण निवेश और टिकाऊ प्रथाओं के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में, राज्य भारत के औद्योगिक विकास में योगदान करने के लिए अपने समृद्ध खनिज संसाधनों का लाभ उठा रहा है।

देश का हृदय स्थल एमपी अपनी समृद्ध खनिज संपदा और निवेश-अनुकूल नीतियों के चलते अब खनन क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने खनिज नीलामी और खनन क्षेत्र में सतत विकास के क्षेत्र में निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। एमपी माइनिंग क्षेत्र में न केवल आर्थिक प्रगति का केंद्र बन रहा है, बल्कि देश के औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

मध्यप्रदेश ने खनिज ब्लॉकों की नीलामी में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। पारदर्शी नीलामी, पर्यावरण-अनुकूल खनन और स्थानीय समुदायों की भागीदारी जैसे सुधारों से निवेशकों का विश्वास मध्यप्रदेश की ओर तेजी से बढ़ा है। 17-18 अक्टूबर 2024 को भोपाल में आयोजित माइनिंग कॉन्क्लेव में 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मध्यप्रदेश को प्राप्त हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य ने 29 खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी की जिसके लिए भारत सरकार ने वर्ष 2022 और 2025 में खनन मंत्रियों के सम्मेलन में मध्यप्रदेश को प्रथम और द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया।

'तू गंदी मकड़ी', कौन है केरल की हनी भास्करन ? जिसने कांग्रेस कांग्रेस विधायक और पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल मैमकुट्टथिल के 'गंदे किस्से' खोले

(जीएनएस)।

केरल की राजनीति में उस समय तहलका मच गया, जब दुबई बेस्ड लेखिका हनी भास्करन ने पलक्कड़ के कांग्रेस विधायक और पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल मैमकुट्टथिल पर महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार और उनकी निजी बातचीत को तोड़-मरोड़कर बदनाम करने के गंभीर आरोप लगाए।

हनी की फेसबुक पोस्ट और मलयालम एक्ट्रेस रिनी एन जॉर्ज के पहले लगाए गए आरोपों ने राहुल को इतने दबाव में ला दिया कि गुरुवार, 21 अगस्त 2025 को उन्होंने केरल युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस घटनाक्रम ने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को हिलाकर रख दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी। आइए जानते हैं, हनी भास्करन ने राहुल को 'गंदी मकड़ी' क्यों कहा और क्या है इस सियासी तूफान की पूरी कहानी...

हनी भास्करन के सनसनीखेज आरोप

हनी भास्करन ने अपनी फेसबुक पोस्ट में राहुल ममकूटाथिल पर महिलाओं के साथ सोशल मीडिया पर 'बैड चैट' करने और उनकी निजता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि 9 जून 2025 को, जब वह श्रीलंका में थीं, राहुल ने उनकी एक इंस्टाग्राम तस्वीर पर दिल वाले इमोजी के साथ कमेंट किया और बातचीत शुरू की। शुरूआत में बातें श्रीलंका यात्रा और नीलांबुर चुनाव को लेकर मजाक तक सीमित थीं। लेकिन जल्द ही हनी को राहुल के संदेशों में छेड़खानी भरा लहजा नजर आया, जिसके बाद उन्होंने जवाब देना बंद कर दिया।

हनी ने लिखा, 'मुझे बाद में पता चला कि राहुल ने मेरे साथ हुई बातचीत को शराब के नशे में अपने दोस्तों के बीच गलत तरीके से पेश किया, जैसे कि मैं उनके पास गई थी। उन्होंने मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की और अपने राजनीतिक सर्किल में झूठी कहानियां फैलाईं।' हनी ने दावा किया कि राहुल का यह व्यवहार सिर्फ उनके साथ नहीं, बल्कि कई अन्य महिलाओं के साथ भी रहा है। उन्होंने लिखा, 'महिलाओं को आपके इस पहलू को जानने की जरूरत है। आप महिलाओं से चैट करते हैं और फिर उसे अश्लील गपशप में बदलकर उनका मजाक उड़ाते हैं। यह शर्मिंदगी और अपमान का कारण बनता है।'

साहित्यिक लेखन के साथ-साथ सामाजिक आंदोलनों में भी उनकी सक्रियता के लिए जाना जाता है। उन्होंने 19 पुस्तकें लिखी हैं। प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मेलनों में वे एक मान्यता प्राप्त वक्ता भी रही हैं। लेखन के माध्यम से महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के हक की बात कहने व सच को उजागर करने में उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता स्पष्ट नजर आती है – हाल ही में उन्होंने राजनीतिक शक्तियों के गलत प्रयोग को उजागर करते हुए साहसिक रूप से सामने आया।

हनी भास्करन ने राहुल को 'तू गंदी मकड़ी' क्यों कहा?

हनी ने राहुल को 'गंदी मकड़ी' कहकर संबोधित करते हुए उनके व्यवहार को बेहद आपत्तिजनक बताया। उन्होंने लिखा, 'मुझे अपनी ही पार्टी की उन महिलाओं के लिए डर है, जिन्होंने आपसे बातचीत की है। उन्होंने आपकी कितनी अश्लीलता सहन की होगी? जिन महिलाओं ने आपके साथ निजी बातें साझा कीं, वे अब खामोश डर में जी रही होंगी।' हनी ने यह भी खुलासा किया कि राहुल के करीबी सहयोगियों ने ही उन्हें उनके व्यवहार के बारे में बताया। उन्होंने लिखा, 'राहुल ममकूटाथिल, तू गंदी मकड़ी है, यह आपके दुश्मनों ने नहीं, बल्कि आपके अपने कांग्रेस सहयोगियों ने मुझे आपकी सच्चाई बताई। अगर आपके करीबी लोग भी मुझे यह बताने को मजबूर हैं, तो सोचिए आपकी बदनामी की हद क्या होगी।'

हनी ने राहुल से न सिर्फ राजनीति, बल्कि पूरे सार्वजनिक जीवन से हटने की मांग की। उन्होंने कहा, 'आप जैसे लोग सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के आसपास भी रहने के लायक नहीं हैं। अगर आपके अंदर जरा भी ईमानदारी बची है, तो एकमात्र सम्मानजनक रास्ता यही है कि आप राजनीति छोड़ दें। यही असली गरिमा है।' हनी के आरोपों से पहले, मलयालम एक्ट्रेस और पूर्व पत्रकार रिनी एन जॉर्ज ने एक युवा राजनेता पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने और पांच सितारा होटल में बुलाने के आरोप लगाए थे।